

अचार के लिए सर्वोत्तम मिर्च पावडर

कम तीखा ज्यादा लाल खाना बने कमाल

सुरक्षित

स्वादिष्ट है सुल्फि से

राजस्थानी मिर्च पावडर

Saruchi Spices Pvt. Ltd. Nagpur. Ph: 07109-278666

विदर्भ की खान

SUNDAY

प्रखर...मुखर...स्वर

सुरक्षित

100gm सुल्फि अचार मसाले 45/- ₹ के पैकेट पर 10/- ₹ की हिंग डब्ली

फ्री अचार मसाला

Saruchi Spices Pvt. Ltd. Nagpur. Ph: 07109-278666

● वर्ष 17 ● अंक 230

नागपुर, रविवार, 16 जुलाई 2017

● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात



राष्ट्रपति नहीं आम नागरिक के तौर पर आऊंगा वापस - मुखर्जी

जांगीपुर

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जांगीपुर के लोगों से कहा कि वे भारत के आम नागरिक के तौर पर वापस आएं। 35 साल के सफल सार्वजनिक जिंदगी के बाद वर्ष 2004 में उन्होंने जांगीपुर से पहली चुनावी जीत हासिल की।

मैकेंजी फुटबॉल ग्राउंड पर केकेएम रूरल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, वे राष्ट्रपति के तौर पर यहां अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि अगले दस दिनों में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लोगों ने काफी उत्साह के साथ राष्ट्रपति का स्वागत और अभिवादन किया जब उन्होंने कहा कि वे 130 करोड़ की देश के जनता में से एक होंगे और एक आम नागरिक के तौर पर वापस आएं। 2010 में अपने पिता कामादा किंकर मुखर्जी की याद में उन्होंने केकेएम गोल्ड कप के लिए रूरल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। जांगीपुर दौरा उनके लिए भावुक क्षण था जहां वे अपने बेटे अभिजीत मुखर्जी द्वारा बनाए गए आवास जांगीपुर हाउस में लोगों से मिले। 2012 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अभीजित ने यहां से लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। सोनातिकुरी गांव में एक एकड़ के प्लॉट पर कुछ बतख वाले एक पोखर के साथ बने साधारण से घर के हॉल में मुखर्जी व उनकी स्वीयमि पत्नी की तस्वीर टंगी है जो आज आगंतुकों का स्वागत अपने मुस्कान के साथ कर रही थी।

मणिपुर के सीएम ने कहा, फर्जी मुठभेड़ की जांच में सहयोग देंगे



इंफाल

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरन सिंह ने राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी को जांच में पूरा सहयोग देगी।

बीरन सिंह ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार सुरक्षा बलों द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं में शामिल लोगों पर मामला दर्ज करने में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य की जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

नीतीश को मनाने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए बिहार के महागठबंधन को बचाने की कसरत में जुटी कांग्रेस ने अब भी नीतीश कुमार को समझाने की कोशिशें नहीं छोड़ी हैं। हालांकि शनिवार को तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर नीतीश के और कड़े होते तेवर के बाद गठबंधन की डोर टूटने की आशंकाएं कहीं ज्यादा गहरी हो गई हैं। शायद इसलिए कांग्रेस हाईकमान नीतीश से दुबारा सीधे बातचीत का जोखिम नहीं उठा रहा है।

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने साफ कहा है कि तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर जदयू यदि जल्दबाजी नहीं दिखाता है तो संकट का रास्ता निकालने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगले हफ्ते नीतीश कुमार से सीधे बातचीत कर सकते हैं। मगर जिस तरह जदयू ने रविवार को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है



और 72 घंटे की अल्टीमेटम अवधि खत्म होने पर कदम उठाने का संकेत दे रही है। उसके मद्देनजर कांग्रेस के रणनीतिकार नीतीश के साथ सोनिया-राहुल की बैठक होने को लेकर संदेह जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए संयम के साथ काम

लेने की सलाह दी जा रही है। जदयू के साथ नीतीश की विपक्षी राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका की ओर इशारा कर भी मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल खासतौर पर नीतीश कुमार और उनके

सलाहकारों से लगातार संपर्क में हैं। मगर अभी तक जदयू की ओर से तेजस्वी पर नरमी के कोई संकेत कांग्रेस को नहीं मिले हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगले हफ्ते के अंत में राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है। कांग्रेस रणनीतिकार नीतीश के इस बैठक के लिए दिल्ली आने को देखते हुए सोनिया-राहुल के साथ उनकी बैठक की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मगर ऐसी बैठक की संभावना तभी बनेगी जब राजद और जदयू तेजस्वी के सवाल पर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। कांग्रेस लालू और नीतीश दोनों से अपने अच्छे रिश्तों की वजह से मध्यस्थता की कोशिश कर रही है। इसमें खास बात यह है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच अच्छे रिश्ते हैं। नीतीश के कामकाज की राहुल कई बार खुली प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहे। लालू पर भ्रष्टाचार के मुकदमों को लेकर राहुल ने एक हद तक दूरी बनाए रखी है, वहीं सोनिया और लालू एक दूसरे का बेहद सम्मान करते हैं।

मंत्री ने कमल हासन को दी भ्रष्टाचार साबित करने की चुनौती

कोयंबटूर

तमिलनाडु के मंत्री एसपी वेलुमणि ने फिल्म अभिनेता कमल हासन को सरकार में भ्रष्टाचार साबित करने की चुनौती दी है। फिल्म अभिनेता ने सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मंत्री ने उन्हें अपना बयान साबित करने वाला सबूत पेश करने को कहा है। नारायणिका प्रशासन मंत्री ने शनिवार को कोयंबटूर में कहा, क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे यह साबित हो सके कि सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार है? यदि ऐसा है तो अभिनेता को इसे साबित करना चाहिए। मंत्री ने हासन से यह भी कहा है कि क्या वह अपनी फिल्मों के लिए भुगतान किए गए कर का ब्योरा भरने को तैयार हैं? वेलुमणि ने कहा कि अभिनेता ने इससे पहले कभी इस तरह का आरोप नहीं लगाया था। इधर हाल के दिनों में हासन ने बिना किसी सबूत के कई चीजों पर बात करनी शुरू की है।

गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 5 लोगों की मौत

अहमदाबाद

गुजरात में भारी बारिश के चलते पांच लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मौतें सीताष्ट्र क्षेत्र में हुई हैं। आपदा अधिकारी के मुताबिक सुंदरनगर, राजकोट, अरावली, गांधीनगर, बनारसकांडा से लोगों की मौत खबर है। मोरबी जिले में कम से कम 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सुंदरनगर के



पास भूगांव नदी में तीन बच्चों के फंसे होने की भी खबर है। इसके साथ ही सुंदरनगर में आई बाढ़ में पति पत्नी के बह गए। मुख्यमंत्री विजय रूपांनी ने हालात का संज्ञान लेने के लिए आपातकाल बैठक बुलाई और जानकारी ली। एनडीआरएफ की बनावसकांडा से लोगों की मौत खबर है। टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया है। राज्य में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है और स्थिति बंद से बदतर होती जा रही है।

आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर सांसद लेंगे स्कूलों को गोद



नई दिल्ली

सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति को भी सुधारने में माननीयों की मदद ली जाएगी। जो अपनी सांसद निधि से अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी स्कूल के मूलभूत ढांचे को सुधारने में मदद देंगे। केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मानव संसाधन मंत्रालय के साथ सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय को इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में यह पूरी योजना लांच कर दी जाएगी।

केंद्र सरकार के स्तर पर यह तैयारी तब शुरू की गई है, जब देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है।

तमाम ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जहां न तो भवन है, न ही पेजयल व शौचालय जैसे मूलभूत इंतजाम। मानव संसाधन मंत्रालय के पास स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर हर साल ऐसी ढेरों शिकायतें आती हैं। इनमें काफी शिकायतें तो खुद सांसदों की रहती हैं, जो अपने क्षेत्र के स्कूलों की खराब स्थिति को सुधारने से जुड़ी होती हैं।

ऐसे में मंत्रालय स्तर पर यह सहमति बनी है, कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने में सांसदों की भी मदद ली जाए। फिलहाल इसका पूरा खाका बनाया जा रहा है। इसके तहत जल्द ही सांसदों से चर्चा व सहमति भी ली जाएगी, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के स्तर पर अभी फिलहाल गांवों के विकास को लेकर सांसदों से जुड़ी सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र के किसी एक गांव को गोद लेता है। जहां वह अपनी सांसद निधि से मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में मदद दे रहे हैं।

सांसद निधि से स्कूलों को इंटरनेट से लैस करने में मदद

सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक सांसदों को मिलने वाली सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से लैस करने में मदद दी जा रही है।

राष्ट्रपति चुनाव: एक ही टेबल पर वोट करेंगे पीएम मोदी और सोनिया



नई दिल्ली

राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक ही टेबल पर बैठकर अपने-अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। बिलेट पेपर से लेकर बिलेट बॉक्स में डालने से पहले की सारी प्रक्रिया टेबल नं. 6 पर होगी। यह मतदान संसद भवन में स्थित कमरा नं. 62 में किया जाएगा। नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा।

संसद भवन से लेकर देश की तमाम विधानसभाओं में वोटिंग शाम 5:00 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 20 जुलाई को सुबह 10:00 बजे संसद के कमरा नंबर 62 में शुरू होगी। विधानसभाओं में भी वोटों की गिनती जारी रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की संख्या कम होती है, इसलिए दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है।

कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव?

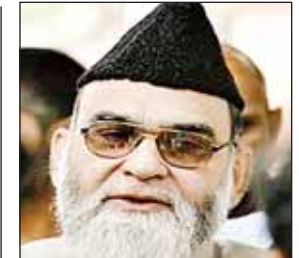
भारत एक लोकतांत्रिक देश है

इसलिए यहां राष्ट्रपति का चुनाव भी लोकतांत्रिक पद्धति या संवैधानिक तरीके से होता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं। उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है।

कौन करता है वोट

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद अपने वोट के माध्यम से करते हैं। प्रेजिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटड मंबर वोट नहीं डाल सकते।

राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते।



इमाम बुखारी का पाक पीएम को पत्र, लिखा- हुर्रियत नेताओं से करें बातचीत

नई दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की ओर से पाक पीएम को पत्र लिखकर हुर्रियत कांग्रेस संग बातचीत करने का दबाव डाला जा रहा है। इमाम बुखारी की ओर से कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को पत्र लिखकर उनसे हुर्रियत कांग्रेस के नेताओं संग बातचीत करने की अपील की है। इमाम बुखारी ने हाथों में हथियार उठाए लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें हथियार छोड़ देना चाहिए, जिससे कि एक शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके।

देश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।

प्रदेश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।

प्रदेश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।

रामनाथ कोविंद ने समर्थन के लिए उद्धव से फोन पर आभार जताया

मुंबई



राष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर समर्थन देने के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया। इसके पूर्व, शनिवार की सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाजे-बाजे के साथ रामनाथ कोविंद का भव्य स्वागत किया। कोविंद सिर्फ ढाई घंटे की यात्रा पर मुंबई आए थे।

विमानतल से उन्हें सीधे दक्षिण मुंबई स्थित गरवारे क्लब ले जाया गया। वहां भाजपा सहित राजग के सभी घटक दलों के सांसदों-विधायकों से मुलाकात की। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी भी बैठक में मौजूद थे। इसी

दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा की और खुद को उनकी पार्टी का समर्थन मिलने पर उन्हें आभार व्यक्त किया। शिवसेना के सूत्रों के अनुसार कोविंद के यात्रा कार्यक्रम में ठाकरे के वांद्रा स्थित निवास मातोश्री जाना नहीं होने पर कुछ लोगों की भीड़ें जरूर चढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि यूपीए प्रत्याशी रहे प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल समर्थन लेने के लिए मातोश्री जा

चुके हैं। रामनाथ कोविंद ने भले ही मुंबई में सिर्फ राजग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की हो, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें समर्थन उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है। भाजपा के 123 विधायकों एवं 23 सांसदों, शिवसेना के 63 विधायकों एवं 18 सांसदों तथा राजग के घटक दल स्वाभिमानी पक्ष के एक सांसद राजू शेड्डी के अलावा कोविंद को कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।

यूपी विधानसभा में 26 फीसद गंभीर अपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक

नई दिल्ली

सदन के अंदर विस्फोटक (पीईटीएन) मिलने से उत्तरप्रदेश विधानसभा चर्चा में है। सत्ता पक्ष जहां मामले की जांच करने में जुटा है वहीं विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। कुल मिलाकर विस्फोटक के बहाने उत्तरप्रदेश विधानसभा सुर्खियों में है। इसी बहाने आइए आपको उत्तरप्रदेश की मौजूदा विधानसभा और विधायकों के इतिहास से रूबरू कराएं।

हमने उत्तरप्रदेश विधानसभा के 402 विधायकों के इतिहास पर नजर डाली है। बता दें कि अपने जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेजा है, उनमें से 143 यानि 36 फीसद पर अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 107 यानि 26 फीसद गंभीर अपराधिक मामलों के आरोपी हैं।

गंभीर अपराधिक मामले क्या होते हैं...

जिन 402 विधायकों की कुंडली हमने खंगाली है उनमें से 107 यानि 26 फीसद विधायकों पर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अपराधिक



रिकॉर्ड और गंभीर अपराधिक रिकॉर्ड में क्या अंतर होता है।

बता दें कि अपराधिक मामले किसी नेता के खिलाफ द्वेष भावना से भी दर्ज हो जाते हैं और कई छोटे-मोटे अपराध भी इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन गंभीर प्रकृति के अपराध कुछ ज्यादा ही संगीन होते हैं।

कैसे-कैसे अपराध और कितने माननीय अपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक

इन 107 में से कुल 8 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या यानि आइपीसी की धारा 302

के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं 34 विधायकों पर हत्या की कोशिश यानि धारा 307 के तहत केस रजिस्टर्ड हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के 1 विधायक अशोक कुमार राणा ने अपने हलफनामों में बताया कि उन पर धारा 354 यानि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज है।

किस पार्टी के कितने गंभीर अपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक

पार्टीवार बात की जाए तो सबसे ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक रिकॉर्ड वाले

विधायक सत्तारूढ़ भाजपा से ही चुनकर आए हैं। भाजपा के 312 में से 83, सपा के 46 में से 11, बसपा के 19 में से 4, कांग्रेस में 7 में से चार और 3 निर्दलीय नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध दर्ज हैं। मौजूदा विधानसभा में 36 फीसद विधायकों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 47 फीसद विधायक अपराधिक छवि के थे। इसी तरह इस बार 26 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रकृति के अपराधों में लिप्त थे।

प्रदेश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।

प्रदेश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।

प्रदेश की जनता भले ही गरीब हो लेकिन, मौजूदा यूपी विधानसभा में धनरासेठ विधायकों की भी कोई कमी नहीं है। जिन 402 विधायकों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उनमें से 322 यानि 80 फीसद विधायकों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछली विधानसभा में 24 फीसद विधायक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में लिप्त थे।